



## मध्यप्रदेश में सहकारिता समितियों के लिए बनाया गया नया कानून बैंक कर्मचारी भी बन सकेंगे प्रशासक

कांग्रेस का आरोप

सहकारिता आंदोलन  
की अंत्येष्टि

सरकार बोली

इससे बढ़ जाएगी  
पारदर्शिता, मंशा साफ



तो किसान हो जाएगा बाहर

मौका मिलेगा, तो किसान अपने आप इससे बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक को पूरी तरह से सहकारिता आंदोलन के खिलाफ बताया। वेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघारे ने कहा कि विधेयक के बावजूद सोसायटी के 2011 से आसी तक बुनाव बही हुआ। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार सहकारिता क्षेत्र के बुनाव करने के लिए कठिन है। बुनाव को लेकर कोई गफलत नहीं है। सहकारिता आंदोलन इससे बहुत होगा। कोई भी व्यक्ति यदि अंशपूर्ण लगा दे, तो उसे एक बार बोल देने का अधिकार रहेगा।

सरकार ने लिए  
अहम फैसले

प्रदेश में लगाए जाएंगे 4 सोलर प्लांट, कैबिनेट की मुहर

विशेष संवाददाता भोपाल। प्रदेश में चार बड़े सोलर संयंक्रमणित किए जाएंगे और पौरीई की सबूत जल परियोजना के लिए भी सोलर संयंक्रमण लगाए जाएंगे। इससे आसानी से विधिवित तौर पर परेयजल की आपूर्ति की जाएगी। यह विश्वास बोमावार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में दुर्व कैवल्य बैंक में दिया गया। विशेष मंत्री कैलेश विजयरामीय ने बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि चार बड़े सोलर प्लांट प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे। कैवल्य बैंक ने चार बड़े ऊर्जा संयंक्रमणों के प्रस्ताव को भी हीड़ी ढाँड़ी दी है। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि नगर परिवार और नगर

400 गांवों को मिलेगा मुआवजा

प्रदेश सरकार राज्य के उन 400 गांवों के किसानों को मुआवजा देंगे, जिनको फसलें पिछले दिनों हुई ओलाप्टि के राजन खराब हो गई हैं। इनके लिए जल संरक्षण कर रिपोर्ट संपर्कों को कहा गया है।

पालिकाओं द्वारा जायदा सोने और ऊर्जा का इत्तमाल किया जाए। विधेयरामीय ने किया कि लोक स्वास्थ्य व्यक्तियों के विभाग की समृद्ध जल परियोजना के लिए भी सोलर संयंक्रमण लगाए जाएंगे। ताकि आसानी से विधिवित परेयजल की आपूर्ति की जा सके। इससे बिजली का खर्च भी अपेक्षाकृत सस्ता होगा।

गर्भियों में की जाएगी टैकरों से जलापूर्ति बैंक में सुझावांकी ने विधिवित को साफ तौर पर विशेषता किया है कि गर्भियों के भौमिकमें प्रदेश के किसी भी अंचल में परेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। आशयकृत ही तो टैकरों से भी जलापूर्ति कराई जाए। यह पूर्ण-पांचियों के लिए भी पांच लोकों का संचय सुनिश्चित होगा। सरकार ने यह भी फैलाव लिया है कि उन्हें को काल गणना का प्रमुख केव्ह बनाया जाएगा। व्यक्तियों विहारी जल संरक्षण टैकरों के लिए अवधिकारी की जा सके। इसको काल गणना की वात कही।

24% बढ़ी सांसदों की सैलरी  
अब हर माह मिलेंगे 1.24 लाख

पूर्व सांसदों की पेंशन 31 हजार की गई

नई दिल्ली, जेनेनेन। सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24

फौसदी का इजाफा कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य

मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक मौजूदा

सांसदों को अब 1.24 लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लगाए जाएंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधिकारित होती है।

डेली अलांडस और पेंशन भी बढ़ाई गई। डेली अलांडस और पेंशन भी बढ़ाई गई। डेली अलांडस पर बढ़ाए रखे जाएंगे। डेली अलांडस पर बढ़ाए रखे जाएंगे।

गणना की भौमिका की भी बढ़ाई हो गई। डेली अलांडस पर बढ़ाए रखे जाएंगे। डेली अलांडस पर बढ़ाए रखे जाएंगे।

प्रत्येक सांसद को 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट एसी में सीटों पर त्रिप्ये प्रति माह और सैलरी के अनुकूल संयंक्रमण के लिए 31 हजार रुपये प्रति माह करी गई है।

बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लगाए जाएंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधिकारित होती है।

प्रत्येक सांसद को 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट एसी में सीटों पर त्रिप्ये प्रति माह और सैलरी के अनुकूल संयंक्रमण के लिए 31 हजार रुपये प्रति माह करी गई है।

बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लगाए जाएंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधिकारित होती है।

प्रत्येक सांसद को 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट एसी में सीटों पर त्रिप्ये प्रति माह और सैलरी के अनुकूल संयंक्रमण के लिए 31 हजार रुपये प्रति माह करी गई है।

बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लगाए जाएंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधिकारित होती है।

प्रत्येक सांसद को 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट एसी में सीटों पर त्रिप्ये प्रति माह और सैलरी के अनुकूल संयंक्रमण के लिए 31 हजार रुपये प्रति माह करी गई है।

बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लगाए जाएंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधिकारित होती है।

प्रत्येक सांसद को 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट एसी में सीटों पर त्रिप्ये प्रति माह और सैलरी के अनुकूल संयंक्रमण के लिए 31 हजार रुपये प्रति माह करी गई है।

बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लगाए जाएंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधिकारित होती है।

प्रत्येक सांसद को 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट एसी में सीटों पर त्रिप्ये प्रति माह और सैलरी के अनुकूल संयंक्रमण के लिए 31 हजार रुपये प्रति माह करी गई है।

बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लगाए जाएंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधिकारित होती है।

प्रत्येक सांसद को 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट एसी में सीटों पर त्रिप्ये प्रति माह और सैलरी के अनुकूल संयंक्रमण के लिए 31 हजार रुपये प्रति माह करी गई है।

बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लगाए जाएंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधिकारित होती है।

प्रत्येक सांसद को 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट एसी में सीटों पर त्रिप्ये प्रति माह और सैलरी के अनुकूल संयंक्रमण के लिए 31 हजार रुपये प्रति माह करी गई है।

बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लगाए जाएंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधिकारित होती है।

प्रत्येक सांसद को 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट एसी में सीटों पर त्रिप्ये प्रति माह और सैलरी के अनुकूल संयंक्रमण के लिए 31 हजार रुपये प्रति माह करी गई है।

बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लगाए जाएंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधिकारित होती है।

प्रत्येक सांसद को 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट एसी में सीटों पर त्रिप्ये प्रति माह और सैलरी के अनुकूल संयंक्रमण के लिए 31 हजार रुपये प्रति माह करी गई है।

बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लगाए जाएंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधिकारित होती है।

प्रत्येक सांसद को 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट एसी में सीटों पर त्रिप्ये प्रति म







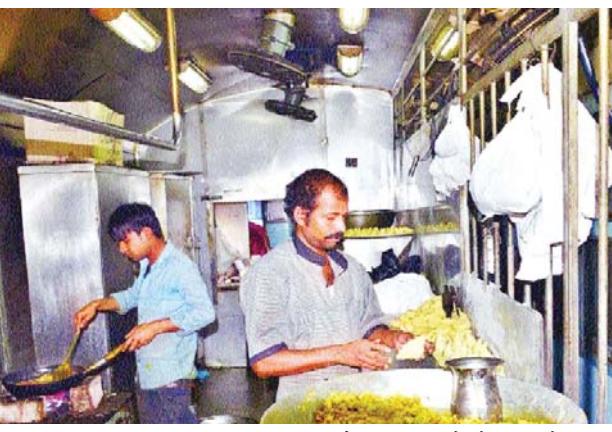


## कमतर साबित हो रहा परिचमी देशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर

प्रसंगवश

### रेलवे की दिनोंदिन लचर होती खान-पान व्यवस्था

**त** माम दावों और मंसूबों के बावजूद भारतीय रेल में विभिन्न सेवाओं से संबंधित शैक्षयों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, खच्छता



और शुद्धता को लेकर लंबे समय रो सिक्षायतें मिलती रही हैं। उन्हें दूर करने के मकसद से भारतील रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी

आडआर्टीसी का गठन किया गया। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर रसोई बनाई गई।

इससे बाहरी खानपान की

गुणवत्ता और कीमतों में

मनमानी पर कुछ हृद तक

रोक तो लगी, खच्छता

और साफ-सफाई पर भी

ध्यान दिया जाने लगा,

मगर फिर वही शिक्षयों

मिलनी शुरू हो गई।

संसद की एक समिति ने

इसे लेकर रेलवे की

खिंचाई की है।

आडआर्टीसी को छह हरित

रसोई भी बानानी थी, मगर

काम नहीं हो सका। समिति का

कहना है कि खानपान सर्वधी

नीतियों में बार-बार बदलाव की वजह से भी यह गड़बड़ी हो रही है।

संसदीय समिति ने इस बात के लिए भी रेलवे पर अमल कर्यों नहीं किया गया।

समिति ने रेलवे से जबाब मांगा है कि जिन पंद्रह खानपान इकाइयों

को अपडेट करने को कहा गया था,

वह क्यों नहीं हुआ। दरअसल,

2005 के बाद से अब तक तीन बार रेलवे खानपान संबंधी नीतियों में

बदलाव किया जा चुका है।

मार्च 2010 में यह काम क्षेत्रीय रेलवे को सौंप दिया गया।

2017 में नई आनपान नीति बनी और उसकी समीक्षा के लिए

संसदीय समिति ने इस बात पर भी रेलवे की विशेष जांच करने की दिया गया।

दरअसल, अभी तक रेलों में परोसा जाने वाला भोजन बाहर की

रसोई में तैयार होकर पहुंचाया जाता है, फिर गाड़ियों में उसे गरम

करने की व्यवस्था होती है।

मगर देखा गया कि वैसे रेलवे बने ही

नहीं हैं। जाहिर है, इस तरह तैयार होने और परोसे जाने के बीच

समय अधिक जुरु जाने से बढ़ गयिए हैं, पर और किंवित किया गया।

संसदीय समिति ने इस बात पर भी रेलवे की विशेष जांच करने की दिया गया।

अक्सर रेल दुरुटनाओं को लेकर सवाल उठते हैं, गाड़ियों के समय

पर न चलने, रेल डिव्हॉज में सुरक्षा का उचित प्रधान भी हो जाए।

इस रिपोर्ट में द्रुतगामी गाड़ियों चलाने देने वा

टेस्टेशनों की देखरेख जिसे कंपनियों के हाथों में सौंप देने भर से

रेलवे की सारक आकर्षित हो जाएगी।

उद्देश्यों को अपनी अपेक्षा अपनी अपेक्षा अपनी अपेक्षा

अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा

अपेक्षा अपेक

## संक्षिप्त खबरें

## शुक्रल को ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सम्मान : सीएम

विंस, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्रल का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयन उनकी सुनात्मक शक्ति और प्रतिभा के सम्मान के साथ ही हिंदी साहित्य जगत का भी सम्मान है। डॉ. यादव ने कहा कि हिंदी साहित्य जगत के कलाई एवं साहित्यकार विनोद कुमार शुक्रल लातीसगढ़ राज्य के प्रथम वर्ष बाला के 12वें साहित्यकार हैं, जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया जाएगा।

## कार्यालय के लिए जमीन की मांग करेगा बीसीसीआई



जागरण संवाददाता, भोपाल। भोपाल चेंबर ऑफ कॉर्मचारी एंड इंडस्ट्रीज द्वारा संस्था का कार्यालय बनाने के लिए शासन से जमीन की मांग की जाएगी। संस्था के अध्यक्ष तेजकुलापाल सिंह पाली ने बताया कि भोपाल के व्यापारियों का सहयोग करने और उनकी सम्पत्तियों का समाधान करने के लिए यह पहल बालायारी स्थित जागरण गार्डन में होली मिलन समारोह के दौरान कही।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। पाली ने बताया कि संस्था द्वारा इस साल 450 नए सदस्य बनाए गए हैं और जिनमें उनके सदस्यों की संख्या 3 हजार से अधिक है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों की आगे की कार्ययोगीता दी और उन्होंने कहा कि सभी सदस्या शहर की स्थानीय सदस्यों के लिए कार्ययोगीता दी जानकारी दी। उन्होंने शनिवार रात को द्वारा विधायक के साथ बालीय का सहयोग करने की जा रही है। यह बात उन्होंने शनिवार रात को लालचाटी स्थित जागरण गार्डन में होली मिलन समारोह के दौरान कही।

## राजगढ़ जिले की सिंचाई परियोजना को पुरस्कार

विंस, भोपाल। राजगढ़ जिले की मोहनपुरा-कुंडलिया सिंचाई परियोजना को जल संसाधनों के कुशल उपयोग, जल संरक्षण और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सीधी आईपी (सेट्रल बोर्ड ऑफ इंडियन एंड पॉर्टर) अवार्ड-इन्स-2024 में 'वर्ष के शैरूद्ध समान्वय जल संसाधन प्रबन्धन' (बेसर आईटीजुआरएम) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलाकार ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार मध्यप्रदेश की अभिनव जल प्रबन्धन प्रणाली और सतत कृषि विकास की अपेक्षा जल प्रबन्धन करता है। यह समान राज्य सरकार की दूरवर्णी जल प्रबन्धन नीतियों और कुशल कार्यान्वयन का परिणाम है। पुरस्कार राज्य संस्थान और आवृत्तिक सिंचाई प्रणालियों के विस्तार को प्रोत्साहित करेगा।

## जमीन आवंटित की गई पर उद्योग नहीं हुए शुरू : जीतू

## सिंहस्थ में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाने वाले भाजपा विधायक को नोटिस

विशेष संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश भाजपा ने आगे ही विधायक चिंतान मालवीय को शो-कॉर्ज नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि उनके द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान ऐसे सवाल क्यों उठाए गए, जिसमें सरकार और पार्टी की छवि धूमिल हुई है। विधायक से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा जाता है। योगराज वह है कि विधानसभा के बजाए सत्र के दौरान आलोट विधायक चिंतान मालवीय ने सिंहस्थ 2028 के लिए अधिग्रहित एवं जमीन का मामला उठाते हुए अपनी ही सरकार को कठोर में खाली कर दिया था। उनका साफ तौर पर कहा था कि सरकार की योजना किसान विरोधी है। इस पर सरकार को एक बार फिर विचार करना चाहिए। विधायक का कहना है कि सिंहस्थ 2028 के लिए सरकार को अस्थाई रूप से जमीनों का अधिग्रहण करना चाहिए।

## जमीनों के स्थाई अधिग्रहण का मामला

गौत्रतलवाल है कि उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ पर पहले प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार किसानों को कृषि साधनों को स्थाई रूप से अधिकारियों एवं अधिकारियों के बीच साधनों के लिए स्थाई अधिकारी और धर्मशाला बनाने के लिए उन्हें देने की योजना बनाती है। मालवीय ने कहा था कि सिंहस्थ टेंट तंतु में आयोजित किया जाता है, इसके लिए सरकार को अस्थाई रूप से जमीनों का अधिग्रहण करना चाहिए।

जिसमें सरकार को दौरान एवं जमीन का मामला उठाने के लिए यह पहल कठोर का जा रही है।



को तैयार है। हालांकि इस मामले में उज्जैन के पार्टी के द्वारा विधायक सरकार के साथ खड़े नजर आए।

उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहड़ा का

कहना है कि सिंहस्थ में लक्ष्मी त्रिवेनी उनकी विधानसभा में आता है। सरकार जो योजना का मामला उठाते हुए अपनी ही सरकार को कठोर में खाली कर दिया था। उनका साफ तौर पर कहा था कि सरकार की योजना किसान विरोधी है। इस पर सरकार को एक बार फिर विचार करना चाहिए। विधायक का कहना है कि सिंहस्थ 2028 के लिए सरकार को अस्थाई रूप से जमीनों का अधिग्रहण करना चाहिए।

जमीनों के स्थाई अधिग्रहण का मामला

इस मामले के लिए जारी योजना का मामला उठाते हुए अपनी ही सरकार को कठोर में खाली कर दिया था। उनका साफ तौर पर कहा था कि सरकार की योजना किसान विरोधी है। इस पर सरकार को एक बार फिर विचार करना चाहिए। विधायक का कहना है कि सिंहस्थ में लक्ष्मी त्रिवेनी उनकी विधानसभा में आता है। सरकार जो योजना का मामला उठाते हुए अपनी ही सरकार को कठोर में खाली कर दिया था। उनका साफ तौर पर कहा था कि सरकार की योजना किसान विरोधी है। इस पर सरकार को एक बार फिर विचार करना चाहिए। विधायक का कहना है कि सिंहस्थ 2028 के लिए सरकार को अस्थाई रूप से जमीनों का अधिग्रहण करना चाहिए।

जमीनों के स्थाई अधिग्रहण का मामला

## संक्षिप्त समाचार

कनाडा में चुनाव का एलान, 28 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट औटोट्राव। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कार्नी ने अचानक देश में 28 अप्रैल को चुनाव करने की घोषणा की। उन्होंने ये फैसला ऐसे समय पर लिया है, जब ट्रंप लगातार कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। कनाडा के पीएम ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उत्तर खत्ते से निपटने के लिए हमें एक भजवृत्त जनने देंगे की आवश्यकता है। कनाडा में इस साल 20 अक्टूबर आम चुनाव होने थे। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कार्नी के बयान से साफ पता चल रहा है कि अमेरिका और कनाडा के बीच संवधं द्वारा दह तक खार पहले तक पुराने सहयोगी और प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुआ करते थे। हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी दी थी।

## पोप फ्रांसिस 5 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए

वेटिकन, जेएनएन। कैथोलिक ईसाई धर्मपुरुष पोप फ्रांसिस को रविवार को 5 हफ्ते बाद हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल की बालकानी से समर्थकों को धन्यवाद कहा। 88 साल के पोप को फैफ़ॉन में इन्फर्नोन की फैफ़ॉन 14 फैफ़ॉन की रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था। इलाज के दौरान कैथेलिक चर्च के हेडकॉर्टर टेकिन ने बताया था कि पोप को ब्लड टेक्स्टिंग में किंडी फैल लेक्षण दिख रहे थे। साथ ही प्लेटलेट्स की कमी का भी पता चला था। इलाज के दौरान वो बार पोप को जन का खत्तर था हॉस्पिटल से निकलने के बाद पोप वेटिकन सिरी में खिंचना साता मार्ट के अपने घर वापस लौटें।

## मुंबई में कॉमेडियन कामरा का स्टूडियो तोड़ा

मुंबई। कॉमेडियन कुणाल कामरा का महाराष्ट्र की राजनीति पर बनाया गया वीडियो विवादों में आ गया। वीडियो में कुणाल ने बिना नाम लिए डिस्ट्री सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया। वीडियो सामने आने के बाद शिंदे गुट के व्यवसेना का वार्तात भारी गए। भारी संख्या में समर्थक रविवार दें रात मुंबई के दूर युनिकॉन्ट्रेनेट ऑफिस पहुंचे। दाव किया जा रहा है कि वही पर वीडियो शूट हुआ था। व्यवसेना समर्थकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की। इसके बाद शिंदे तर्ज करने के लिए खार पुलिस स्टेनिंग पहुंचे। उनकी मांग है कि कुणाल कामरा को तुरंत अरेस्ट किया जाए।

## दिल्ली में पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव

नई दिल्ली, जेएनएन। दक्षिण दिल्ली में हैंज खास इलाके के डियर पार्क में रविवार ताके 21 वर्षीय युवक और 18 वर्षीय युवती के शव पेड़ से लटके मिले। पुलिस को आत्महत्या का सदेह है। पुलिस को सदेह है कि दोनों के बीच प्रेम संवधं था। उनके रिसर्वे को परिवारों द्वारा अवाकाश किये जाने के कारण उन्होंने यह कह दिया था। हालांकि, कुछ स्थानीय लोगों ने इस घटना में साजिश की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उनसे पहले कहा था कि दोनों 17 साल के थे। पुलिस के अनुसार, 'डियर पार्क' के एक स्थान पार्क मॉर्निंग नहीं है कि दोनों के बीच प्रेम संवधं था। उनके रिसर्वे के कारण उन्होंने यह कह दिया था। हालांकि, कुछ स्थानीय लोगों ने इस घटना में साजिश की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उनसे पहले कहा था कि दोनों 17 साल के थे। पुलिस को अनुसार, 'डियर पार्क' के एक स्थान पार्क मॉर्निंग नहीं है कि दोनों के बीच प्रेम संवधं था। उनके रिसर्वे के कारण उन्होंने यह कह दिया था। हालांकि, कुछ स्थानीय लोगों ने इस घटना में साजिश की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उनसे पहले कहा था कि दोनों 17 साल के थे। पुलिस ने बताया कि पिलंजे गांव का निवासी वह युवक लोधी कॉलोनी में कर्मज की एक दुर्घटना हो चुकी है। ये संशोधन वक्फ़ संपर्कियों के पांच वर्षों के बाद अपने कर्मज की एक दुर्घटना हो चुकी है। ये संशोधन वक्फ़ संपर्कियों के पांच वर्षों के बाद अपने कर्मज की एक दुर्घटना हो चुकी है। ये संशोधन वक्फ़ संपर्कियों के पांच वर्षों के बाद अपने कर्मज की एक दुर्घटना हो चुकी है। ये संशोधन वक्फ़ संपर्कियों के पांच वर्षों के बाद अपने कर्मज की एक दुर्घटना हो चुकी है। ये संशोधन वक्फ़ संपर्कियों के पांच वर्षों के बाद अपने कर्मज की एक दुर्घटना हो चुकी है।

## बदहाली | भारत के इस गांव के लड़कों से शादी नहीं करती लड़कियां, नहीं पैदा हो रहे बच्चे, स्कूल में सिर्फ 5 छात्र

## कुंवारों का गांव, यहाँ के लड़कों से लड़कियां शादी ही नहीं करती

जोंदालगढ़ी, जेएनएन। किसी लड़के ये लड़की से शादी ना करने की कोई वजह ही सकती है लेकिन क्या कोई गांव ही शादी ना करने का कारण हो सकता है? शायद आपने ऐसा पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आकर्ता बताने जा रहे हैं कि एक ऐसा गांव है जहाँ के लड़कों से कोई शादी ही नहीं करना चाहता। इसीले इस गांव का नाम कुंवारों का गांव पड़ गया है। यह बाबौरी जिसे कोई वजह नहीं है कि एक लड़की के बदलावी की वजह से इनकार कर देती है? तो इसके पीछे की वजह सिर्फ़ गांव की बदलावी है और कुछ नहीं।

## क्या है शादी ना करने की वजह?

केरल के जोंदालगढ़ी गांव के लड़कों के लिए शादी केरली वृक्षों बहुत बड़े तास के समान ही है, व्याकों आन्य जल्लीय व्यवस्थाएं न के बाबर हैं, जिसकी वजह से यहाँ के शादी योग्य युवकों को कोई भी लड़की अपनाने के लिए तैयार होती है। करीब 200 लोगों की आबादी वाले इस गांव में से ज्यादा नैजवान वर्षों से शादी को कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई अपने कोई लड़की ही मिल पाते हैं।

## धर्म आधारित आरक्षण अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है : दत्तत्रेय

कर्नाटक सरकार के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण का मामला

बेंगलुरु, जेएनएन। सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने के कार्यकारी सरकार के फैसले पर जारी बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकारी वर्ग दत्तत्रेय लोसवाले ने रविवार को कहा कि संविधान धर्म अधिकारी को इस तरह की आवश्यकता है। कनाडा में इस साल 20 अक्टूबर आम चुनाव होने थे। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कार्नी के बयान से साफ पता चल रहा है कि अमेरिका और कनाडा के बीच संवधं दह तक खार पहले तक पुराने देश की समय में यहाँ आया और प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुआ करते थे। हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी दी थी।



आरएसएस क्यों कर रहा विरोध

आरएसएस का कहना है कि भारत का संविधान धर्म अधिकारी को इस तरह की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का आरक्षण बी आर अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान के खिलाफ है। आरएसएस की निर्णय लेने वाली संघव्यवसंथ संघ (आरएसएस) ने भारत के वर्ग लोसवाले को आवश्यकीय प्रतिनिधि दिया है। आरक्षण बी की अवृत्ति वर्ग लोसवाले ने इसका कठोर समर्थन किया है। आरक्षण बी अवृत्ति वर्ग लोसवाले को आवश्यकीय संघ संघव्यवसंथ अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान में धर्म अधिकारी आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसा करने वाला कोई भी गमरा है। आरक्षण बी संवधान के खिलाफ जारी करते हैं।

## मूल्यों के खिलाफ जाने वाले लोगों को आदर्श बनाया गया

होसवाले ने कहा कि भारत के मूल्यों के खिलाफ जाने वाले लोगों को आदर्श बनाया गया। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर का विरोध करने के लिए राजा महाराणा प्रताप जैसी स्थियरातों की सुधारना की। आरएसएस ने कहा कि आक्रमणकारी मानसिकता वाले लोग भारत के लिए खत्तर देता है। संगव्यवसंथ के वर्ग लोसवाले ने इसका कठोर समर्थन किया है। आरक्षण बी अवृत्ति वर्ग लोसवाले को आवश्यकीय संघ संघव्यवसंथ अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान में धर्म अधिकारी आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसा करने वाला कोई भी गमरा है। आरक्षण बी संवधान के खिलाफ जारी करते हैं।

## मोहन भागवत से मिले भाजपा अध्यक्ष नड़ा



भाजपा लोसवाले ने कहा कि भारत के वर्ग लोगों के खिलाफ जाने वाले लोगों को आदर्श बनाया गया। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर का विरोध करने के लिए राजा महाराणा प्रताप जैसी स्थियरातों की सुधारना की। यूनानी वर्ग के मूलताबिक ये बैठक चंगलुर में हैं। उन्होंने 21 मार्च से आरएसएस ने भारत के लिए खत्तर देता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो भारतीय संवधान के लिए धर्म अधिकारी प्रतिनिधि संघ की वैचक चंगलुर रही थी। बैठक का आज आयोडी दिन था। सूरी के मूलताबिक भागवत के वैचक चंगलुर में हैं। उन्होंने बड़ा विरोध करते हैं। ये लोगों की वैचक चंगलुर में भागवत के लिए धर्म अधिकारी प्रतिनिधि संघ की वैचक चंगलुर में हैं। उन्होंने बड़ा विरोध करते हैं। ये लोगों की वैचक चंगलुर में भागवत के लिए धर्म अधिकारी प्रतिनिधि संघ की वैचक चंगलुर में हैं। उन्होंने बड़ा विरोध करते हैं। ये लोगों की वैचक चंगलुर में भागवत के लिए धर्म अधिकारी प्रतिनिधि संघ की वैचक चंगलुर में हैं। उन्होंने बड़ा विरोध करते हैं। ये लोगों की वैचक चंगलुर में भागवत के लिए धर्म अधिकारी प्रतिनिधि संघ की वैचक चंगलुर में हैं







